भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *32
उत्तर देने की तारीख 27 नवम्बर, 2024

संचार सेवाओं का विस्तार

***32. श्री राहुल कस्वांः**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में संचार सेवाओं के विस्तार के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा लिए गए निर्णय की कोई समीक्षा की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, विशेषकर राजस्थान में, टेलीफोन और मोबाइल सेवाओं के विस्तार के संबंध में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के चूरू जिले में कितने टावरों को स्थापित करने की मांग की गई थी और वास्तव में कितने टावरों को स्थापित किया गया है तथा शेष टावरों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है, इस सम्बन्ध में स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार ने बीएसएनएल नेटवर्क पर 5जी सेवा शुरू कर दी है और यदि हां, तो विशेष रूप से चूरू जिले में स्थान और टावर-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

<u>संचार सेवाओं का विस्तार के संबंध में दिनांक 27 नवंबर 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *32 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण</u>

(क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1997 में की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई अधिनियम की धारा 11 (1) (क) के अनुसार स्व-प्रेरणा से अथवा सरकार के अनुरोध पर सिफारिशें करता है। सरकार देश में संचार सेवाओं के विस्तार हेतु नीतियां बनाते समय ट्राई द्वारा जारी विभिन्न सिफारिशों पर विचार करती है। पिछले 10 वर्षों में देश में दूरसंचार कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है, जैसे:

- बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की कुल संख्या मार्च-2014 के 6.49 लाख से बढ़कर नवंबर-2024 में 29.43 लाख हो गई है।
- कुल मोबाइल ग्राहक मार्च 2014 के 90.45 करोड़ से बढ़कर अगस्त 2024 में 116.38 करोड़ हो गए हैं।
- इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या मार्च-2014 के 25.15 करोड़ से बढ़कर जून-2024 में 96.96 करोड़ हो गई है।
- सितंबर 2024 तक देश के 6,44,131 गांवों में से (गांव के आंकड़े भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार) 6,22,840 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान कर दी गई है।

(ग) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा मोबाइल कवरेज उनकी तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर प्रदान की जाती है। सरकार देश के ग्रामीण, जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल टॉवरों की संस्थापना के माध्यम से दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) के तहत विभिन्न स्कीम लागू कर रही है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में डिजिटल भारत निधि के तहत चल रही परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

राजस्थान में मोबाइल सेवाओं के विस्तार के लिए चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. 354 सेवा से वंचित गांवों की परियोजना: यह परियोजना राजस्थान सहित जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के सेवा से वंचित भागों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए है। इस परियोजना के तहत दिनांक 31.10.2024 तक राजस्थान के 30 गांवों में 30 मोबाइल टावरों की संस्थापना की गई है।
ii. आकांक्षी जिला परियोजना में 502 चिन्हित सेवा से वंचित गांव: यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आकांक्षी जिलों में सेवा से वंचित गांवों में 4जी

मोबाइल कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए है। इस परियोजना के तहत दिनांक 31.10.2024 तक राजस्थान के 50 गांवों को 43 मोबाइल टावरों की संस्थापना द्वारा कवर किया गया है।

iii. सेवा से वंचित गांवों की परियोजना में 4जी मोबाइल सेवाओं का सेच्युरेशन: यह परियोजना राजस्थान सहित देश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा से वंचित 24,680 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए है जिसमें पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा प्रचालकों द्वारा सेवाओं को वापस लेने आदि के कारण 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का अतिरिक्त प्रावधान है। इस परियोजना के तहत दिनांक 31.10.2024 तक राजस्थान के 348 गांवों को 292 मोबाइल टावर संस्थापित करके कवर किया गया है।

इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल की चरण-IX.2 परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में अब तक 666 मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बीटीएस) संस्थापित किए गए हैं।

(घ) राजस्थान के चूरू जिले में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संस्थापित मोबाइल टावरों का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ) जी नहीं। हालांकि, भारत में दुनिया का 5जी सेवाओं का सबसे तेज़ रोल आउट हुआ है जिनमें राजस्थान के चूरू जिले में 698 बीटीएस सहित देश में अन्य टीएसपी द्वारा लगभग 4.62 लाख बीटीएस संस्थापित किए गए हैं।

अनुबंध-I

"संचार सेवाओं के विस्तार" के संबंध में माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 27 नवंबर, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *32 के भाग (ग) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में चल रही डीबीएन परियोजनाएं:

मोबाइल परियोजना/स्कीम			
क्र.सं.	**परियोजना/स्कीम**	**करार लागत (रु. करोड़ में)**	**बीटीएस का दायरा**
1	502 आकांक्षी जिले	414	250
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	130	88
3	एलडब्ल्यूई चरण-II	2,211	1,266
4	अरुणाचल प्रदेश और असम	1,255	773
5	7287 आकांक्षी जिले	3,685	3,678
6	4जी सेच्युरेशन	30,620	17,901
7	बीओपी/बीआईपी	1,546	585
8	लक्षद्वीप द्वीप समूह	36	37
9	एलडब्ल्यूई चरण-I उन्नयन	2,426	2,343
संशोधित भारतनेट			
क्र.सं.	**परियोजना/स्कीम**	**स्वीकृत राशि (रु. करोड़ में)**	**कवरेज**
10	संशोधित भारतनेट कार्यक्रम	1,39,579	(ii) मांग के आधार पर लगभग 3.8 लाख गैर-ग्राम पंचायत गांवों में मौजूदा नेटवर्क और कनेक्टिविटी का उन्नयन करने सहित रिंग टोपोलॉजी में देश में सभी ग्राम पंचायतों के लिए कनेक्टिविटी का प्रावधान

अनुबंध-II

"संचार सेवाओं के विस्तार" के संबंध में माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए दिनांक 27 नवंबर, 2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *32 के भाग (घ) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध

जिले का नाम	**पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा संस्थापित मोबाइल टावरों की संख्या**			
	2021	**2022**	**2023**	**चालू वर्ष 2024**
चूरू	142	132	116	19

*****